भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2949
गुरुवार, 12 दिसंबर, 2024/21 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

नए विमानपत्तनों का निर्माण

2949. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों से संपर्क को बढ़ावा देने के लिए देश में नए विमानपत्तनों के निर्माण की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उन शहरों का ब्यौरा क्या है जहां इन विमानपत्तनों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यात्रा सुविधाओं में सुधार करने और राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से राजस्थान राज्य में नागर विमानन गतिविधियों को बढ़ावा देने का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार श्रीगंगानगर विमानपत्तन का पुनर्विकास करने का है ताकि इससे पंजाब और हरियाणा के आस-पास के क्षेत्रों को लाभ मिल सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): भारत सरकार ने दो-चरण अनुमोदन प्रक्रिया अर्थात 'साइट क्लीयरेंस' और तत्पश्चात 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के माध्यम से देश में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए ग्रीनफील्ड विमानपत्तन (जीएफए) नीति, 2008 तैयार की है। जीएफए नीति 2008 के अनुसार, भूमि अधिग्रहण और इसका वित्तपोषण, आदि सहित ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित हवाईअड्डा विकासकर्ता अथवा राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, की है।

भारत सरकार ने जीएफ़ए नीति, 2008 के अनुसार अब तक देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान की है, जिनमें गोवा में मोपा, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, शिरडी और सिंधुदुर्ग, कर्नाटक में कलबुर्गी, विजयपुरा, हसन और शिवमोग्गा, मध्य प्रदेश में डबरा (ग्वालियर), उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और नोएडा (जेवर), गुजरात में धोलेरा और राजकोट (हीरासर), पुडुचेरी में कराईकल, आंध्र प्रदेश में दगडार्थी, भोगापुरम और ओरवाकल (कुर्नूल), पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पाक्योंग, केरल में कन्नूर और अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर (होलोंगी) शामिल हैं।

इनमें से 12 ग्रीनफ़ील्ड हवाईअड्डे अर्थात, दुर्गापुर, शिरडी, कन्नूर, पाक्योंग, कलबुर्गी, ओरवाकल (कुर्नूल), सिंधुदुर्ग, कुशीनगर, ईटानगर (होलोंगी), मोपा, शिवमोग्गा और राजकोट (हीरासर) में प्रचालन शुरू हो गया है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने 9 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के निर्माण के लिए 'साइट क्लीयरेंस' भी दे दी है, जिसमें राजस्थान में अलवर, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, हिमाचल प्रदेश में मंडी, केरल में कोट्टायम, ओडिशा में पुरी, असम में दोलू, तमिलनाडु में परंदूर, राजस्थान में कोटा और कर्नाटक में रायचूर शामिल हैं।

हवाईअड्डों का विस्तार और विकास एक सतत प्रक्रिया है तथा ऐसे कार्य भूमि की उपलब्धता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, सामाजिक-आर्थिक सरोकार, यातायात मांग/एयरलाइनों की ऐसे हवाईअड्डों तक/से प्रचालन करने की तत्परता, जैसे कारकों पर निर्भर रहते हुए, एएआई और अन्य हवाईअड्डा विकासकर्ताओं द्वारा समय-समय पर किए जाते हैं। एएआई ने राजस्थान में जोधपुर और उदयपुर हवाईअड्डों पर नए टर्मिनल भवन के निर्माण का कार्य शुरू किया है।

इसके अतिरिक्त, नागर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने और जनसाधारण के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने हेतु दिनांक 21.10.2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) शुरू की है। आरसीएस-उड़ान मांग-आधारित योजना है। विशेष मार्ग पर मांग के अपने आकलन के आधार पर, इच्छुक एयरलाइनें उड़ान योजना के तहत बोली प्रक्रिया के समय अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। 'उड़ान' योजना के तहत अवार्ड किए गए मार्गों में शामिल कोई हवाईअड्डा जिसे 'उड़ान' प्रचालन शुरू करने हेतु स्तरोन्नयन/विकास की आवश्यकता है, उस हवाईअड्डे का विकास 'असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों का जीर्णोद्धार' योजना के तहत किया जाता है।

उड़ान योजना के तहत, राजस्थान में अवस्थित आरसीएस हवाईअड्डे नामतः बीकानेर, किशनगढ़ और जैसलमेर का विकास और प्रचालन पहले ही शुरू किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान में आरसीएस उड़ानों के विकास और परिचालन के लिए श्रीगंगानगर और उत्तरलाइ (भारतीय वायु सेना) हवाईअड्डों को चिह्नित किया गया है।

*****